➤Postal Regd. No. MCN/298/2016-2018 ➤RNI No. MAHMUL/2015/65928

गऊ वंश पर आधारित प्रथम राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में।

www.gaubharatbharati.com

संपादक - संजय शर्मा

गऊ भारत भारती

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, नाशिक, पुणे, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात में वितरित

मूल्य ₹/- रुपये

● Email: gaubharatbharti@gmail.com ● वर्ष- 7 ● अंक- 32 ● मुंबई, रविवार 23 जनवरी 2022 से 29 जनवरी 2022 ● पृष्ठ- 4

Deepak Farsan Mart Kurla

दीपक फरसाण मार्ट कुर्ला

595, Pipe Road, Opposite Deepak Farsan, Kurla (W), Kurla West, Kurla, Mumbai, Maharashtra 400070 Phone: 098195 52117

संक्षिप्त खबरें

गणतंत्र दिवस पर कड़ी सुरक्षा के साये में मुंबई! पुलिस की जनता से अपील; संदिग्ध की जानकारी दें

मुंबई- गणतंत्र दिवस पर मुंबई पुलिस पूरी तरह चौकस रहेगी। पुलिस मुख्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, हाल ही में दिल्ली में गाजीपुर सब्जी मंडी और त्रिलोकपुरी में मिले संदिग्ध बैग की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने भी एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुंबई पुलिस द्वारा न सिर्फ मुंबई बल्कि आसपास के जिलों की भी सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। इसके लिए

संबंधित जिले के पुलिस प्रमुख से बातचीत कर वहां की कानून व्यवस्था के बारे में अपडेट लिया जा रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस इसे नियमित जांच प्रक्रिया बता रही है, लेकिन खुफिया विभाग से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि एटीएस, आईबी, और सीआईडी जैसे अहम सुरक्षा एजेंसियों से नियमित तौर पर तालमेल बिठा कर स्थानीय प्रशासन कार्य कर रही है। महत्वपूर्ण स्टेशनों एवं इनसे लगे भीड़भाड़ वाले बाजारों में सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सागरी पुलिस से जुड़े अधिकारी वी.आर.पाटील के मुताबिक, अरब सागर के रास्ते मुंबई हमले जैसी कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए सागर तटों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जा रहा है।

मुंबई में २० मंजिला इमारत में भयानक आग, २८ लोग झुलसे, ६ लोगों की मौत

मुंबई- महाराष्ट्र के मुंबई में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. यहां मुंबई के तारदेव में भाटिया अस्पताल के पास कमला बिल्डिंग की २० मंजिला इमारत में आग लग गई. बताया जा रहा है कि आग १८वें मंजिल

पर लगी थी. हादसे में २८ लोग जख्मी हुए हैं. सभी को भाटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि इमारत में फायर सिस्टम था, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था. जानकारी के अनुसार इस आग में झुलसे ६ लोगों की मौत हो चुकी है. पहले ७ लोगों की मौत की खबर सामने आई थी. राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को ५-५ लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है. वहीं, घायलों के इलाज का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी. इसके अलावा पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को २-२ लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है. वहीं, घायलों को ५०-५० हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. बताया जा रहा है कि सुबह ७.३० बजे कमला बिल्डिंग की १८वीं मंजिल में ये आग लगी. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग की वजह अभी पता नहीं चल पाई है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आग की वजह का पता चल पाएगा. हालांकि, बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है.

दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव में गोहत्या पर उम्रकैद की सजा

दोषियों को भरना होगा एक से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना

नई दिल्ली- केंद्र शासित प्रदेश दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव में गोहत्या विरोधी कानून के कड़े प्रविधान लागू होंगे। समाचार एजेंसी एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव के लिए गोहत्या के खिलाफ कड़े कानून को अधिसूचित किया है। दोषियों को १० साल से लेकर उम्रकैद की सजा और एक से पांच लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। संशोधित कानून के दायरे में गाय, बछड़ा, बछिया, बैल और सांड को शामिल किया गया है।

इन मवेशियों के ट्रांसपोर्टेशन और बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध होगा। केंद्र शासित दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव (राज्य कानूनों के अनुकूलन) दूसरा आदेश २०२२ के अनुसार, मंगलवार को दोनों पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेशों में लागू बांबे पशु संरक्षण अधिनियम १९५४ में संशोधन किया गया है। अब यह संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश में लागू होंगे। यह कानून गुजरात के साथ ही गोवा में भी लागू है।

मेघालय की एक अदालत ने

में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के वरिष्ठ नेता निदामोन चुलेट को शराब के नशे में २५ वर्षीय व्यक्ति की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। वेस्ट जयंतिया हिल्स जिले की अदालत की ओर से एनपीपी के कार्यकारी अध्यक्ष पर ५० हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एनपीपी के वरिष्ठ नेता निदामोन चुलेट को मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा का करीबी माना जाता है। अदालत ने चुलेट के सहयोगी कोमिंग राबोन को भी शव ठिकाने लगाने का दोषी पाया।

SHAGUN GUPTA FOUNDATION

PRESENT'S

IN ASSOCIATION WITH

Gau Bharat Bharati

भारत के वीर शहीदों के नाम

1st Foundation Day And

Seva Samman Samaroh

Dr. Shagun Gupta Founder Chief Trustee

- Invited Chief Guest -

Mr. Ajay Kaul (President Ekata Manch)

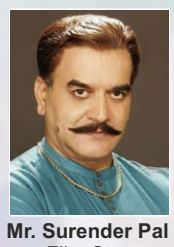

Mr. Surender Pal Film Star

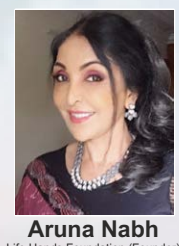

Aruna Nabh Life Hands Foundation (Founder) Social Activist

Mr. Amarjit Mishra EX. vice-chairman of Maharashtra Film, Stage & Cultural Development

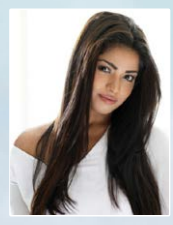

Miss Lokesh Kumari Actress Big Boss Fame

Mr. Ram Kumar pal National Vice President PM Atamnirbhar Bharat

Mr. Prashant Kashid Vice President Ekata Manch

Pallavi kulkarni Film Actress

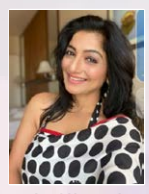

Aarti Naagpal Film Actress

V. I. P. Staindup Commedian

Karishma Rao Actress

Mr. Vikas Kapoor Film Writer & Producer

Nita Jayesh Desai Write Co Founder Of Life Hands Foundation Social Activist

Dr Bhakti Talekar Gynecologist MD DGO

Mr. Midhat Khan Film Actor

Pentali Sen Film Actress

Sanjay Amaan Chief Editor, Writer, Poet, Author Film And Music Producer

Date: 26 Jan 2022 Timing 3 to 6PM

Venue: The Classique Club, New Link Road, Andheri West, behind Infinity Mall, Mumbai, Maharashtra 400053

Supported By-

एंबुलेंस मिलते ही गौ सेवा मंडल का काम हुआ आसान

अंबिकापुर- बीमार और दुर्घटनाओं में घायल होने वाले मवेशियों के सेवा कार्य में गौ सेवा मंडल जी जान से जुटा हुआ है। अंबिकापुर के सेवाभावी अजय अग्रवाल के परिवार द्वारा एंबुलेंस उपलब्ध करा देने के बाद गौ सेवा मंडल का कामकाज थोड़ा आसान हुआ है। अब बीमार अथवा दुर्घटना में घायल मवेशियों को पशु चिकित्सालय ले जाने में पहले जैसी तकलीफ नहीं होती। सूचना मिलते ही गौ सेवा मंडल के सदस्य एंबुलेंस से मवेशियों को पशु चिकित्सालय पहुंचा रहे हैं।

यूं तो गौ सेवा मंडल विगत चार वर्षो से सरगुजा संभाग में बेजुबानो की जान बचाने का कार्य करते आ रहा है लेकिन एंबुलेंस के अभाव में हमेशा से ही उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है लेकिन पशुओं को लाने ले जाने एंबुलेंस मिल जाने से वे अपना सेवा कार्य और त्वरित तरीके से कर पा रहे हैं। गौ सेवा मंड़ल के अध्यक्ष रिंकू तिवारी ने बताया कि उनकी टीम चार साल से २४ घंटे बेजुबानों की सेवा में

लगा है। सूचना मिलते ही तुंरन्त टीम मौके पर पहुंवःजाता है और बेजुबान को रेस्क्यू कर उसका इलाज करवा बचाने का कार्य करता है। उन्होंने बताया कि अभी तक उनकी टीम ने लगभग दो हजार से ज्यादा बेजुबानों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई है, जिसमें गाय, कुत्ता,बिल्ली, खरगोश, बंदर आदि सभी अन्य बेजुबानो को बचाने का कार्य करते आ रहे हैं पर बेजुबानो को रेस्क्यू करने में एम्बुलेंस न होने के कारण दिक्कत का सामना करना पड़ता था। गौ सेवा मंड़ल के संरक्षक मास्क मैन अजय अग्रवाल द्वारा एंबुलेंस की सौगात दी गई तो गौ सेवा मंडल के काम में सुविधा मिलने लगी है। अब एंबुलेंस से बेजुबानों को रेस्क्यू कर बचाया जा रहा है। कल ही एक गाय के बच्चे को कुत्ता काट दिया था जिसकी सूचना पर मंडल की टीम एम्बुलेंस लेकर गई और रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई गई। कही भी कोई पशु, पक्षी बीमार दिखे तो तुंरन्त गौ सेवा मण्डल के सदस्यों से संपर्क किया जा सकता है।

गाय के पांव में बंधी थी रस्सी; गांठ खोलने के बजाए काट डाला गाय का पांव

रीवा- प्रदेश के रीवा जिले के हरदी गांव में एक जिंदा गाय का पांव काट देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आवारा गाय का एक पैर काटने और अन्य गायों के साथ उसे फेंकने के इल्जाम में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि घटना १३ जनवरी को बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में हुई थी. पुलिस ने बताया कि एक ही परिवार के तीन सदस्य अशोक गुप्ता, राजकुमार गुप्ता और दशरथ गुप्ता सहित अन्य लोग आवारा गायों को ट्रक में भरकर तालाब के पास छोड़ने आए थे. उनमें से एक गाय को ट्रक से उतारने के दौरान गाय के पैर में रस्सी बंधी होने के कारण जल्दबाजी में आरोपियों ने उसका पैर काट दिया और उसे नीचे धक्का दे दिया. बैकुंठपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शुक्ला ने बताया, ''गायों को छोड़ने के दौरान आरोपी घबरा गए और वहां से भागने लगे, लेकिन एक गाय ट्रक के अंदर ही थी और उसका दाहिना पैर बंधा हुआ था. गाय को ट्रक से जल्दी धकेलने के चक्कर में आरोपियों ने उसका पैर काट दिया और उसे नीचे फेंक दिया. उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग पशु चिकित्सक की मदद से गाय का उपचार कर रहे हैं.

मामला सामने आने पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी सहित ग्रामीणों के एक समूह ने पुलिस में शिकायत दी जिसके आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मप्र पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबद्ध धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. इस बीच, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने एक विज्ञप्ति में दावा किया कि उनके प्रयासों और पशु कार्यकर्ता (द्विवेदी) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के कारण रीवा पुलिस ने गायों की तस्करी और एक गाय का पैर काटने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

प्रधानमंत्री की डीएम के साथ बैठकः पीएम बोले- बजट बढ़ता रहा लेकिन

आजादी के ७५ साल बाद भी कई जिले पीछे ही रह गए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी २२ जनवरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) से बात की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी डीएम को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जिले में होने वाली समस्याओं से अवगत करवाया। पीएम ने कहा कि एक तरफ बजट बढ़ता रहा, योजनाएं बनती रहीं, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता रहा, लेकिन फिर भी आजादी के ७५ साल बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन जिलों के साथ पिछड़े जिलों का टैग लगा दिया गया।

पीएम मोदी ने कहा कि आज आकांक्षी जिले देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। आप सबके प्रयासों से आज आकांक्षी जिले गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि उनके राज्यों में आकांक्षी जिलों ने कमाल का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिलों में विकास के लिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद और एक भावुक जुड़ाव भी बहुत जरूरी है। एक तरह से गवर्नेंस का टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप फ्लो बहुत जरूरी है। इस अभियान का महत्वपूर्ण पहलू है - टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। पीएम मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिलों में जो काम हुआ है वो बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के लिए अध्ययन का विषय है। पिछले चार सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जन-धन खातों में ४ से ५ गुना की वृद्धि हुई है। लगभग हर

परिवार को शौचालय मिला है, हर गाँव तक बिजली पहुंची है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों ने, अलग-अलग विभागों ने ऐसे १४२ जिलों की एक लिस्ट तैयार की है। जिन एक-दो पैरामीटर्स पर ये अलग-अलग १४२ जिले पीछे हैं, अब वहां पर भी हमें उसी कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना है, जैसे हम आकांक्षी जिलों में करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले चार सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जन-धन खातों में ४ से ५ गुना की वृद्धि हुई है। लगभग हर परिवार को शौचालय मिला है, हर गांव तक बिजली पहुंची है और बिजली सिर्फ गरीब के घर में नहीं पहुंची है बल्कि लोगों के जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिलों में जो लोग रहते हैं, उनमें आगे बढ़ने की तड़प होती है। इन लोगों ने अपने जीवन का अधिकतर समय अभावों में, मुश्किलों में गुजारा है। हर छोटी-छोटी चीजों के लिए उन्होंने परिश्रम किया है।

गौ सेवा परिवार की अनोखी पहल, गायों को ठंड से बचाने खिलाए जा रहे लड्डू

प्रदेशभर में शीतलहर चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इंसानों के साथ ही मूक पशु भी मौसम की मार झेल रहे हैं। जिले में गौवंश को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए गौ सेवा परिवार की टीम ने अभिनव पहल शुरू की है। सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले मूक पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उन्हें गुड़ के लड्डू खिलाए जा रहे हैं। गौ सेवा परिवार की टीम मूक पशुओं को कपड़े लपेटकर और अलाव जलाकर ठंड से बचाने का प्रयास भी कर रही है। टीम के सदस्य देर रात तक गायों को लड्डू खिलाते हैं ताकि वो कड़ाके की ठंड का सामना कर सकें। टीम अब तक जिले की १०० से ज्यादा गायों को गुड़ के लड्डू खिला चुकी है। गौ सेवा परिवार जनसहयोग से जिले में यह अभियान चला रहा है, जो कि आगे भी जारी रहेगा।

संपादकीय...
संजय शर्मा

चीन की मंशा

अरुणाचल प्रदेश से एक लड़के का अपहरण कर चीन ने अब नया विवाद खड़ा कर दिया है। यह घटना मंगलवार की है। अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद तापिर गाव ने बुधवार को सोशल मीडिया पर दावा किया था कि चीनी सैनिक अठारह जनवरी को सियांग जिले में भारतीय क्षेत्र में घुस आए और लुंगता जोर इलाके से सत्रह साल के एक लड़के मिराम तैरोन को अगवा करके ले गए। यह घटना गंभीर इसलिए भी है कि चीन लगातार ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा है जिससे भारत उकसावे में आकर कोई कदम उठाए और फिर उसे भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खोलने का मौका मिले। इससे एक बार फिर यह भी साबित हो गया कि भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ जारी है। जिस क्षेत्र से लड़के को अगवा किया गया, वहां से त्सांगपो नदी भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश करती है। बताया गया है कि यह लड़का यहां अपने एक

दोस्त के साथ शिकार के लिए आया था। पर उसका दोस्त बच निकला और उसी ने स्थानीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। लेकिन जो हो, बड़ा सवाल यह है कि भारतीय सैनिकों की कड़ी चौकसी के बावजूद चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आने में कामयाब कैसे हो जा रहे हैं? यह लड़का तो चीन की सीमा में घुसा नहीं था! भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ कोई नई बात नहीं हैं। ये आए दिन का राग हो चला है। खासतौर से जब से गलवान घाटी विवाद शुरू हुआ है, तब से सीमाई इलाकों में चीनी सैनिकों की गतिविधियां ज्यादा ही बढ़ गई हैं। पिछले साल अक्तूबर में अरुणाचल प्रदेश के ही तवांग में करीब दो सौ चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए थे और टकराव की स्थिति बन गई थी। उससे पहले अगस्त में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक उत्तरांखड के बाड़ाहोती में घुस कर तोड़फोड़ की थी। गौरतलब है कि चीन ने साल २०१८ में अरुणाचल प्रदेश के इसी सियांग जिले में भारतीय क्षेत्र में तीन-चार किलोमीटर तक घुस कर सड़क तक बना ली थी। याद किया जाना चाहिए कि सितंबर २०२० में भी चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले से पांच लोगों को अगवा कर लिया था और उन्हें एक हफ्ते बाद छोड़ा था। हालांकि व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो सीमाई इलाकों में लोगों का एक दूसरे देश की सीमाओं में भूलवश चले जाना कोई गंभीर अपराध नहीं है। ऐसा खासतौर से उन इलाकों में ज्यादा होता है जहां पर सीमाओं को लेकर स्पष्ट सीमांकन या बाड़बंदी नहीं होती, जिनसे यह पता चल सके कि हमारी सीमा यहां तक है। पर जंगली इलाका होने की वजह से कई बार चरवाहों का दूसरे देश की सीमा में पहुंच जाना आम बात है। इस हकीकत को सीमा पर तैनात सभी जवान और अधिकारी समझते हैं। अगर कोई घुस भी आता है तो उसे पूछताछ के बाद उसके देश के अधिकारियों के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन सियांग जिले में चीनी सैनिक जिस तरह से घुसे और लड़के को अगवा करके ले गए, उसके पीछे मंशा कोई छिपी नहीं है। भारत और चीन के बीच इस वक्त गंभीर गतिरोध का दौर चल रहा है। गलवान घाटी की घटना के बाद उपजे विवाद को सुलझाने के लिए चौदह दौर की बैठक हो चुकी हैं, पर चीन के हठीले रवैए से कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि चीन ऐसी हरकतों के जरिए भारत पर दबाव बनाने की रणनीति पर चल रहा है।

राहुल के सामने प्रियंका गांधी ने कहा- मैं हूं पार्टी का चेहरा, क्या कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर संकेत है?

लखनऊ/नई दिल्ली: राहुल गांधी खुद अभी-अभी छुट्टी से लौटे हैं। विदेश गए हुए थे। निजी काम से। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी पंजाब में सत्ता बचाने और उत्तर प्रदेश में सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। खुद को कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता बताते हैं। सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। प्रियंका गांधी महासचिव हैं। लेकिन पार्टी में भयंकर विरोध है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए जी-२३ सक्रिय है। भारी दबाव में कांग्रेस पार्टी में संगठन की आंतरिक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी साल सितंबर-अक्टूबर में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव होंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश में सक्रिय प्रियंका गांधी ने बड़ा संकेत दिया है। शुक्रवार को राहुल गांधी के बगल में रहते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संकेत दिया। एक पत्रकार ने पूछा क्या बिना चेहरे के कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उतर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा अहम होता है, इस पर प्रियंका गांधी ने कहा- आपको किसी और का चेहरा दिखता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस पर रिपोर्टर ने पूछा .. क्या आप ही चेहरा होंगी? तब प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा - दिख तो रहा है न मेरा सब जगह चेहरा। आदतन बड़े

मौकों पर निजी कारणों से विदेश यात्रा करने वाले राहुल गांधी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बैठे हुए थे। हालांकि पिछले साल जब कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई थी तब अशोक गहलोत जैसे राहुल के समर्थकों ने उनसे पार्टी अध्यक्ष बनने की गुहार लगाई थी। संख्याबल पक्ष में था नहीं , इसलिए सोनिया ने सख्त लहजे में कह दिया कि फुल टाइम अध्यक्ष मैं ही हूं। दरअसल कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने फुल टाइम अध्यक्ष नहीं होने पर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जताई थी।

सीताराम केसरी के बाद अब तक कांग्रेस में अध्यक्ष सर्वसहमति से ही चुना जाता रहा है। इस बार पार्टी नेताओं का मूड कुछ अलग है। ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी ने खुद को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर साफ संकेत दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी की बागडोर वो संभाल सकती हैं। दबी और खुली दोनों जुबान में पार्टी नेताओं को प्रियंका गांधी में उनकी दादी और चार बार प्रधानमंत्री बनीं इंदिरा गांधी का अक्स दिखता है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रयिंका के कंधों पर ही यूपी चुनाव की जिम्मेदारी है। बल्कि ये जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली है।

पूरब के चक्रव्यूह में सुरक्षित कमल; भाजपा की सबसे सुरक्षित सीट से कौन बनेगा उम्मीदवार, डिप्टी सीएम भी दावेदार

लखनऊ- लखानऊ पूर्व विधानसभा सीट बीजेपी के लिए कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल २०१२ में सपा की लहर के दौरान लखनऊ शहर के पांच सीटों में महज यहीं से बीजेपी प्रत्याशी जीता था। चार सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि पूर्व सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को भारी अंतर से हराया था। इस सीट पर बीजेपी से प्रत्याशी के नाम पर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। निवर्तमान विधायक आशुतोष टंडन को यहां मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसके साथ डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा के चुनाव लड़ने का ऐलान के बाद पूर्व सीट को भी उनकी पसंदीदा सीटों में एक बताया जा रहा। पिछले ३० साल से यहां कमल खिल रहा है। ऐसे में बीजेपी के टिकट को जीत की गारंटी माना

जा रहा है। बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली सीट से पूर्व सांसद लालजी टंडन के बेटे और निवर्तमान विधायक आशुतोष टंडन भी दोबारा टिकट चाहते हैं। इस बीच पूर्व सांसद और इसी सीट से विधायक रह चुके कलराज मिश्रा के बेटे अमित मिश्रा का नाम भी चर्चा में है। तमाम नामों की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने अब तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं, सपा और कांग्रेस ने भी सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी से टिकट का ऐलान होने के बाद जातीय समीकरण के मुताबिक दूसरी पाटिर्यां यहां से प्रत्याशी का ऐलान करेंगी। लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट पर साल १९९१ से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के खिलाफ इस सीट पर विपक्ष का कोई समीकरण काम नहीं आया। साल २०१७ में सपा-कांग्रेस गठबंधन करके भी चुनाव नहीं जीत सकी थी। हाईप्रोफाइल मानी जाने वाली सीट को लेकर फिलहाल कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।

अयोध्या की सीटों पर बीजेपी के चुनाव प्रचार का मजबूत खाका तैयार, RSS का मिला साथ

अयोध्या- बीजेपी की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा अयोध्या सीट के साथ जिले की अन्य चारों विधानसभा गोसाईगंज, रूदौली, बीकापुर और मिल्कीपुर सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी संगठन ने मजबूत आईटी व बूथ लेवल तक टीमें तैयार की हैं। हालांकि यहां चुनाव पांचवे चरण में है, लेकिन बीजेपी की टीमों ने सरकार की उपलब्धियों का प्रचार शुरू कर दिया है। बूथ लेवल पर गठित टीमें घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं के पंफलेट बांट रही हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय मंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने चुनाव प्रचार संरचना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से आईटी सेल, सोशल मीडिया व बूथ लेवल तक प्रचार तंत्र तक तैयार नेटवर्क तैयार किया गया है। श्रीवास्तव के मुताबिक, प्रदेश से लेकर विधान सभा, मंडल व बूथ स्तर तक के लिए प्रचार की टीमें गठित की गई हैं जिसने काम भी शुरू कर दिया गया। बताया गया कि अयोध्या सीट को विशेष दर्जे की सीट मानकर इसके लिए मजबूत प्रचार नेट वर्क तैयार किया गया है। अयोध्या विधान सभा क्षेत्र में कुल ३ लाख ८९ हजार ७६६ वोटर हैं। कुल ४१४ बूथ हैं। औसत ९०० वोटर हर

बूथ से जुड़े हैं। जिनसे संपर्क करने के लिए २१ सदस्यीय टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि हर बूथ पर बीजेपी के ५ सोशल मीडिया वालंटियर तैनात किए गए हैं। बताया गया हर बूथ पर त्रिदेव की तैनाती की गई है जो पूरी टीम पर नियंत्रण रखने के साथ कोआर्डिनेटर के तौर पर कार्य करेंगे।

दूसरों के सहारे दुकान चलाने का अखिलेश का सपना नहीं होगा पूरा; ब्रजेश पाठक का हमला

बरेली- उत्तर प्रदेश के मंत्री बृजेश पाठक ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास 'पहले फेज की ज्यादातर सीटों के लिए नाम किए फाइनल'अपना कुछ नहीं है और वह दूसरों की मदद से दुकान चलाने'' की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह इसमें सफल नहीं होंगे। ब्राह्मण समाज के लोगों से मिलने के बाद उन्होंने कहा, ''सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास अपना कुछ नहीं है। वह दूसरे के सहारे अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन

उनका यह सपना पूरा नहीं होगा। मोदी और योगी के नेतृत्व में भाजपा २०२२ में प्रचंड बहुमत से सरकार बनायेगी।' उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों से कहा, 'आप किसी के बहकावे में न आयें ।' बुधवार देर रात पत्रकारों से बातचीत में भाजपा में इस्तीफों पर कैबिनेट मंत्री ने कहा, 'भाजपा, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमने एक प्रशिक्षित कैडर तैयार किया है। पूरे पांच वर्ष जनता के बीच मे रहकर काम किया है, ये लोकतंत्र का महापर्व है। जब परिणाम आएगा तो भाजपा के पक्ष में आएगा।'

आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा, बिजनौर, बागपत, मेरठ में कई नेताओं पर एफआईआर

मेरठ- यूपी विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा हैं। बिजनौर में नूरपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मिठाई बांटने पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। बिजनौर की सदर सीट से बसपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक रुचि वीरा के खिलाफ भी आचार संहिता का उल्लंघन करने और महामारी एक्ट के तहत मंडावर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। बागपत में रालोद उम्मीदवार और पूर्व विधायक समेत २५० के खिलाफ और मेरठ में भी सपा कैंडिडेट योगेश वर्मा पर एफआईआर लिखी गई हैं। बिजनौर में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह के खिलाफ फ्लाइंग स्क्वाड मजिस्ट्रेट सुरेश चंद की ओर से दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में उनके समर्थकों द्वारा कोविड गाइडलाइन

का उल्लंघन करते हुए मिठाई बांटी गई। अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज होने की पुष्टि की है। गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह पूर्व विधायक स्वर्गीय लोकेंद्र चौहान के भाई हैं। बिजनौर सदर सीट से बसपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक रुचि वीरा के खिलाफ भी आचार संहिता का उल्लंघन करने और महामारी एक्ट के तहत मंडावर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

जीरो बजट या कुदरती खेती क्या है?

जीरो बजट खेती का अर्थ है की चाहे कोई भी फसल हो उसका उपज मोल ज़ीरो होना चाहिए। (कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन विल बी जीरो) कुदरती खेती मैं इस्तेमाल होने वाले साधन बाजार से खरीद कर नहीं डाले जाने चाहिए। वो सरे साधन और तत्व पौधे की जड़ों के आस पास ही पड़े होते हैं। अलग से बन बनाया कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। हमारी धरती पूर्ण तरह से पालन हार है।

हमारी फसलें धरती से किनते प्रतिशत तत्त्व लेती हैं?

हमारी फसल सर डेढ़ से दो प्रतिशत ही धरती से लेती हैं। बाकि अठानवे से साढ़े अठानवे प्रतिशत हवा और पानी से लेती हैं। असल मैं आपको फसल लेने के लिए अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। यही खेती का मूल विज्ञान है। हरे पत्ते दिन भर खाद का निर्माण करते हैं। हर एक हरा पता अपने आप ने एक खाद्य कारखाना है। जो की इन्ही चीजों से खुराक बनता है। वो हवा से कार्बन डॉइ ऑक्साइड और न्यट्रोजन लेता है। बरसात से इकठा हुआ पानी उसकी जड़ों तक पहुँच जाता है। सूरज की रौशनी से ऊर्जा (१२/५ किलो कैलोरीज / वर्ग फुट एरिया प्रति दिन) ले कर खुराक का निर्माण करता है। किसी भी फसल या पेड़ का पता दिन की दस घंटे धुप दौरान प्रति वर्ग फुट एरिया के हिसाब से साढ़े चार ग्राम खुराक तैयार करता है। इस साढ़े चार ग्राम से डेढ़ ग्राम दाने को या ढाई ग्राम फल या पेड़ के किसी और हिस्से को मिल जाता है जहाँ योग्यता हो। खुराक बनने योग्य तत्व वो हवा या पनि से लेता है। जो की बिलकुल फ्री है। इस लिए न तो बादल का कोई बिल है और न हवा पनि का। सब मुफ्त मिलता है। जब पौधे ये तत्व लेते हैं तो किसी डॉक्टर

या यूनिवर्सिटी की फरमाइश से नहीं लेते। अगर हम ये मान भी लेते हैं तो जंगलों मैं ये परिकिरिया कौन सी विश्विदियलय या डॉक्टर करते हैं ये बिलकुल कुदरती होता है।

अब बात ये उठती है की अगर ये सब धरती मैं है तो डॉक्टर मिटी की जाँच किों करवाते हैं। हाँ वो ये जान ने के लिए की कौन से तत्व हैं। फिर डॉक्टर ये कहते हैं की आपकी मिटी मैं तत्व तो हैं लेकिन पौध इनको गरहन नहीं कर सकता इस लिए ऊपर से डालने पड़ेंगे। असल मैं ये बात वैसे ही है जैसे हमारे घर में खाना पड़ा हो लेकिन पक हुआ न हो और पकाने वाले भी घर पे न हों। और हम बाहर से पका हुआ खाना मगवा कर खाएं। उसी तरह तत्व तो हमारी धरती में सभ हैं लेकिन उनको पकाने वाले जीव हमने मार दिए हैं रसायन या कीट नाशक या और केमिकल डाल कर। अगर हम इनकी व्रतों बंद करके देसी तरीके से चलते हैं तो हम जरूर उन खाना बनने वाली किरिया को चालु कर सकते हैं। इस लिए हमें जीव जन्तुओ को पुनर स्थापित करना होगा।

हम अनत कोटि जीवों को कैसे खेत में डाल कर खाद बनने के काम लगा सकते हैं?

वो चमत्कारी साधन है हमारी देसी गाय का गोबर। इसमें करोड़ो सक्षम जीव होते हैं जो धरती मत को चाहिए हैं। ये धरती को ऐसे जाग लगाती है जैसे दूध को दही। जैसे पूरी हांडी का दूध सिर्फ एक चमच दही से ही दही बन जाता है वैसे ही गाए का गोबर काम करता है। एक गाए एक ग्राम के गोबर में तीन सो करोड़ से पांच सो करोड़ तक सक्षम जीव होते हैं।

एक एकर को कितना गोबर चाहिए?

इस्पे खोज की गई थी जिस से सामने आया है की ,महाराष्ट्र की गोलउ ,लाल कंधारी ,खिलारी, देवनी डांगी ,निमारी और पश्चिमी भारत की गिर ,थपरकर ,साहीवाल रडसिन्धी, और दक्षिणी भारत की अमृत महल और कृष्णा काठी , और उत्तर भारत की हरयाणा नामी गय खोज का हिंसा बानी थी।

इनके ऊपर किये गए तजुरबे नीचे दिए गए हैं

पहला तजूर्बा:- देसी गए का गोबर और मल मटर सबसे उत्तम है। लेकिन बैल और भैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जरसी गाये का नहीं होना चाहिए। किओंकी वो गाये नहीं कोई और जीव है। गाओं में से कपिला गाय उत्तम है। जिसका रंग कल हो।

दूसरा तजुरबा :- गोबर जितना ताज़ा हो उतना अच्छा है और मूत्र जितना पुराण हो उतना अच्छा है।

तीसरा तजुरबा :- एक गए तीस एकर तक की खेती के लिए जायज़ है। इसके होते हुए रसायन खाद इस्तेमाल करना मतलब फ्री में जेब कटवाना है। एक देसी गाये एक दिन मैं गियरह किलो गोबर देती है। और हमें एक महीने मैं दस किलो गोबर एक एकर में डालना चाहिए मतलब साल में एक क्वीन्टल बीस किलो एक एकर के लिए काफी है। और ट्राली भर के गोबर डालने की जरूरत नहीं है।

गोबर को किस ढंग से खेत में डालना है?

जीवों के मल मुतर से पेड़ों या फसलों के फल देने का गहरा सम्बन्ध है। आप ने देखा होगा के जिस पेड़ को मीठे फल लगते हैं उसके फल खा क्र जीव वाही मल मूत्र करते हैं जिस से पेड़ को खुराक मिलती है इसी सिद्धांत पे चलते। कुदरत मीठा फल देती है और बदले में जीव पौधे को खुराक देते हैं खोज कर्ताओं ने गए के गोबर मैं गुड डाला जिस से की सुखसम जेव जियादा बढे और जल्दी बढे। अगर और भी अच्छे परिणाम लेने हो तो प्रोटीन वाली दाल का भी कुछ प्रतिशत डालना चाहिए। जिस से जीव जल्दी सक्रिय होते हैं।और इन्ही परिणामों के चलते नीचे दी गई औषदि के रूप में तैयार किये जा सकते हैं।

गोरक्षार्थ धमयुद्ध सुत्रपात

धर्मप्राण भारत के हरदे सम्राट ब्रह्मलीन अन्त श्री स्वामी श्री करपात्री जी महाराज द्वारा संवत २००१ में संस्थापित अक्षिल भारतवासीय धर्मसंघ ने अपने जन्मकाल से ही मॉ भारतीय के प्रतीक गो रक्षा पालन पूजा एंव संर्वधन को अपने प्रमुखा उद्देश्यो में स्थान दिया था। सन २१४६ में देश में कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनी। भारतीय जनता ने अपनी सरकार से गोहत्या के कलंक को देश के मस्तक से मिटाने की मांग की। किंतु सत्ताधारी नेताओं ने पूर्व घोषणाओ की उपेक्षा कर धर्मप्राण भारत की इस मांग को ठुकरा दिया। सरकार की इस उपेक्षावर्ती से देश के गोभक्त नेता एवं जागरूक जनता चिन्तित हो उठी। उन्हे इससे गहरा आघात लगा। सन' १९४६ के दिसम्बर मास में देश के प्रमुख नगर बंबई श्रीलक्ष्मीचण्डी-महायज के साथ ही अखिल भारतीय धर्मसंघ के तत्वाधान में आयोजित विराट गोरक्षा सम्मेलन मे स्वामी करपात्री जी ने देश के धार्मिक सामाजिक एंव राजनैतिक नेताओं एंव धर्मप्राण जनता का आह्वान किया। देश के सवोच्च धर्मपीठो के जगदगुरू शंकराचार्य संत महात्मा विद्वान राजा-महाराजा एंव सद'गहस्थो ने देश के समक्ष उपस्थित इस समस्या पर गम्भीर विचार मंथन किया। और सम्मेलन में सर्वसम्मत घोषणा की गयी कि गयी' सरकार से यह सम्मेलन अनुरोध करता है कि देश के सर्वविध कल्याण को ध्यान में रखते हुए भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रतीक गोवंश की हत्या कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगा दे। कदाचित सरकार ने अक्षया त्रतीय २३ तदनुसार २८ अप्रैल १९९८ तक सम्मेलन के अनुरोध पर ध्यान नही दिया तो अखिल भारतीय धर्म संघ देश की राजधानी दिल्ली मे सम्पुर्ण गो हत्याबंदी के लिए अंहिसात्मक सत्याग्रह प्रारम्भ कर देगा। उक्त घोषणा के पश्चात् शिष्ट मण्डलो गो रक्षा सम्मेलनो जन सभाओ हस्ताक्षर आन्दोलन एवं स्मरण पत्रों द्वारा सरकार के कर्ण धारो को गोहत्या बंदी की मॉग का औचित्य एवं अनिर्वायता समझाने की भरसक चेष्टा की गयी; किंतु सरकार के कानपर जू तक नही रेंगी।

Budget 2022: India set for modest fiscal consolidation amid slow economic recovery

After Budget 2020 was blown apart in a couple of months by the onset of the coronavirus pandemic, Finance Minister Nirmala Sitharaman was fully prepared the next year, presenting a package focused on capital expenditure to pull the Indian economy out of the rut it found itself in.

The objective of the 2022 Budget–set to be presented on February 1–is not too dissimilar although some limiting factors have emerged. "The upcoming budget faces acute policy trade-offs between nurturing a nascent growth recovery and diminishing fiscal space with challenging debt dynamics," noted Madhavi Arora, lead economist at Emkay Global Financial Services.

A combination of pandemic-related spending and a clean-up of its books saw the Union government's fiscal deficit balloon to 9.2

percent of gross domestic product (GDP) in fiscal year 2021. While this allowed the Centre to target a sharp reduction in the deficit to 6.8 percent next year, a similar pullback is not expected in fiscal 2023. According to a Moneycontrol survey of 10 economists, the Centre should meet its fiscal deficit target for fiscal 2022. And while some consolidation is expected in fiscal 2023, it is likely to be modest, with the median of economists' estimates suggesting the 2022 Budget will set a fiscal deficit target of 6.1 percent of GDP for the next financial year.

"We believe that policymakers will favour a gradual consolidation, which will be premised on continued tax buoyancy as economic growth improves and reduction in pandemic-related increase in revenue spending,'' Morgan Stanley economists said in a report on January 18. Aided by a favourable base effect, India's GDP is expected to grow 9.2 percent in fiscal 2022, decelerating to 7.6 percent in fiscal 2023, as per the Reserve Bank of India's (RBI) most recent survey of professional forecasters.

The Centre's tax collections have improved remarkably in fiscal 2022, with gross tax collections in April-November 2021 up a massive 50.3 percent year-on-year thanks to a low base and the ongoing economic recovery. On the whole, the Centre's receipts in the year could exceed the Budget estimate by as much as Rs 3 lakh crores. This would broadly match the net cash outgo as per the government's first and second supplementary demands for grants for the year. However, fiscal 2023 will be an entirely different ballgame.

Top Indian Army brass to discuss LAC situation at high-level meeting next week

NEW DELHI: Amid heightened military activities by the Chinese military opposite eastern Ladakh on its side on the Line of Actual Control, top Indian Army leadership would be briefed about the force's operational preparedness at a high-level meeting to be held here next week. "The preparedness of the Indian Amy to deal with any situation would be discussed at the meeting to be attended by all commander-in-chief rank officers," a source told ANI.

The sources said that the meeting is scheduled to be held from June 16 for two days where other security issues faced by the country would also come up for discussion. Army chief General Manoj Mukund Naravane has been monitoring the preparedness of the force all along the LAC and has personally

visited the Ladakh sector seven-eight times to take stock of the situation there. The Chinese military is holding large-scale military exercises in its traditional training areas including the locations from where they had diverted towards the Indian front in an aggressive manner last summer.

The Indian Army is hopeful of resolving the issue soon as they have been holding talks with the Chinese military.

The military and diplomatic parleys have helped in the withdrawal of troops from the Pangong lake area but the stalemate in the other friction points still continues.

India and China have been engaged in a military standoff for more than a year now after the Chinese showed aggression along the Indian areas. The Indian side retaliated heavily and deployed more than 50,000 troops and heavy weaponry to check the Chinese aggression.

Gen Naravane's legacy can only be understood over time. But it's altered LAC dynamics forever

Come April, General Manoj Mukund Naravane will retire as the 27th chief of the Indian Army. Only time will tell if the Narendra Modi government will appoint him as India's Chief of Defence Staff or not.

But one thing is for sure — Gen Naravane will leave behind a legacy that most will understand only with time.

As the Army chief, he worked without any fanfare or publicity, even though he was personally responsible for some key strategic and tactical decisions that will shape the Army's outlook in the coming years.

Gen Naravane's tenure has been an action-filled one. From the ongoing standoff with China along the Line of Actual Control (LAC) to the reiteration of the ceasefire at the Line of Control (LoC) with Pakistan, from rewriting of the Order of Battle (ORBAT) to focusing on conventional warfare rather than just counter-terrorism operations, his tenure as Army chief has seen it all, including focused modernisation.

Gen Naravane has been both a dove and a hawk, depending on the issue. This was because, at the end of the day, he was, and is, a "quintessential Army man" — a term I used to describe him in a profile I did when he took over as the Army chief on 31 December 2019.

He took over from his antithesis Gen Bipin Rawat, who spoke freely at the cost of being accused by many of going beyond the realm of the Army chief at times.

Immediately after taking over, Gen Naravane held his first press conference on the occasion of Army Day, which is celebrated on 15 January. He was asked by a journalist if he agrees with Gen Rawat's statement on the students' protests against the Citizenship (Amendment) Act (CAA). Gen Naravane said the Army's role is to "uphold the core values" of the Constitution.

"We respect the fundamental rights of the citizens. If we remember this, then we will not go wrong in the discharge of our duties. We are an Army of the people and for the people, and whatever we do, will be for them," he had said. He underlined that the armed forces owe their allegiance to the Constitution of India and fight to protect the core values of justice, equality and fraternity enshrined in the Preamble.

'बुली बाई' ऐप मामला: अदालत ने तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया

मुंबई- मुंबई की एक अदालत ने 'बुली बाई' ऐप से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार तीन छात्रों की जमानत याचिकाओं को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। इस ऐप में मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें डालकर उन्हें निशाना बनाया गया था। तीन आरोपियों में विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत शामिल हैं। मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने सिंह (१८) और रावत (२१) को पांच जनवरी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था जबकि झा को चार जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। उपनगरीय बांद्रा में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत का विस्तृत आदेश अभी प्राप्त

नहीं हो सका है। इससे पहले, पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था कि आरोपियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए सिख समुदाय से संबंधित नामों का इस्तेमाल समाज में शांति भंग करने और धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के इरादे से किया है। पुलिस ने अदालत से कहा कि तीनों आरोपी ट्विटर, इंस्टाग्राम और जीमेल पर कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालित कर रहे थे। साइबर प्रकोष्ठ ने कहा है कि अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने वाले कई खातों को हटा दिया गया या निलंबित कर दिया गया और इस संबंध में अभी जानकारी जुटानी है। मुंबई पुलिस ने कई उन महिलाओं की शिकायतों के बाद प्राथमिकी दर्ज की, जिन्हें 'बुली बाई' ऐप में निशाना बनाया गया था।

संरक्षित समुद्री जीवों को समुद्र में छोड़ने पर मछुआरों को ४० लाख रुपये का मुआवजा

मुंबई- महाराष्ट्र के तटवर्ती जिलों में मछुआरों को पिछले तीन वर्षों में ओलिव रिडले और हरे समुद्री कछुओं समेत २६० संरक्षित समुद्री जीवों को वापस समुद्र में छोड़ने पर मुआवजे के रूप में ४०.७८ लाख रुपये दिए गए हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि ये जीव इन मछुआरों के मछली पकड़ने के जाल में फंस गए थे। इस मुआवजे का भुगतान राज्य के वन विभाग और मत्स्य पालन विभाग द्वारा दिसंबर २०१८ में संयुक्त रूप से शुरू की गई योजना के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दुर्लभ

प्रजाति के समुद्री जीवों का संरक्षण करना है। विज्ञप्ति में बताया अब तक १३८ ओलिव रिडले कछुए, ६७ हरे समुद्री कछुए, पांच हॉक्सबिल कछुए, दो लेदरबैक समुद्री कछुए, ३७ डियर शार्क, छह विशाल गिटार फिश, चार फिनलेस पोरपोइज समेत अन्य जीव वापस समुद्र में छोड़े गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान बृहस्पतिवार को कहा कि मैंग्रोव सेल (कांदलवन प्रतिष्ठान) ने उन मछुआरों को ४०.७८ लाख रुपये का मुआवजा दिया है, जिन्होंने समुद्री जीवों को वापस समुद्र में छोड़ा था।

बीएमसी ने उच्च न्यायालय से कहा, मुंबई में कोविड की स्थिति नियंत्रण में

मुंबई- बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों

में कोविड-१९ की मौजूदा स्थिति 'नियंत्रण में' है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने सूचित किया कि मुंबई में कोरोना वायरस की मौजूदा तीसरी लहर में मामलों में धीरे-धीरे गिरावट देखी जा रही है। साखरे ने पीठ को यह भी बताया कि १५ जनवरी तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, शहर में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या ८४,३५२ थी जिनमें से सात प्रतिशत रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी और तीन प्रतिशत को ऑक्सीजन सपोर्ट और ०.७ फीसदी को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने नगर निकाय की ओर से एक विस्तृत नोट पेश किया जिसमें इलाजरत मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाओं के स्टॉक, अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तर आदि का विवरण है। साखरे ने कहा, 'हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति है, अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध हैं। घबराने की कोई वजह नहीं है।' पीठ ने तब पूछा कि क्या नगर निकाय कह रहा है कि मुंबई में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है? जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने हां में जवाब दिया।

मुंबई लोकल में बिना वैक्सीन वालों की एंट्री बैन, सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- जनहित में लगाई है पाबंदी

मुंबई- महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय में कहा कि पूरी तरह कोविड वैक्सीनेशन नहीं करवाने वाले लोगों के उपनगरीय ट्रेनों से यात्रा करने पर रोक कानून सम्मत और तर्कसंगत है। सरकार के वकील अनिल अंतुरकार ने कहा कि वैसे तो ऐसी पाबंदी संविधान के अनुच्छेद १९ (१) (डी) के तहत स्वतंत्र रूप से आने-जाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है लेकिन यह महामारी के मद्देनजर तर्कसंगत है।

उन्होंने कहा, 'यह नागिरकों के मौलिक अधिकार पर लगाई गई तर्कसंगत पाबंदी है और ऐसी पाबंदी व्यापक जनहित खासकर उनके अपने ही फायदे के लिए लगाई गई है।' वह मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ के सामने यह दलील रख रहे थे। पीठ उन जनहित याचिका पर अंतिम सुनवाई कर रही थी जिसमें स्थानीय ट्रेनों में बिना कोविड-१९ टीकाकरण वाले यात्रियों की यात्रा पर लगाई गई पाबंदी को चुनौती दी गई है।

अगस्त २०२१ में एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा के वास्ते टीकाकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया। याचिकाकर्ता के वकीलों नीलेश ओझा और तनवीर निजाम ने दलील दी थी कि यह अधिसूचना अवैध, मनमानीपूर्ण एवं समानता एवं स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार का उल्लंघन है। अंतुरकार ने अदालत से कहा, 'महाराष्ट्र ने (महामारी की) पहली लहर के दौरान चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई मौतों से भारी नुकसान उठाया। इसलिए हम इस बार अधिक सावधानी बरतना और मामलों को न्यूनतम करने के लिए यथासंभव एहतियात बरतना चाहते हैं।'

उन्होंने कहा कि वैसे तो टीकाकरण से पूर्ण प्रतिरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती है लेकिन यह अस्पताल में भर्ती और मौत को रोकने की दिशा में एक कदम है, इसलिए किसी भी अतिरेक आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए ट्रेन में यात्रा पार पाबंदी लगायी गयी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि इस महामारी से निपटने की केंद्र सरकार की 'राष्ट्रीय योजना' में टीकाकृत एवं गैर टीकाकृत जैसा कोई भेदभाव नहीं है।

IIMAમાં આ વર્ષે એમબીએ પ્રવેશ બેચલર ડગ્રિીના રઝિલ્ટ વગર જ થશે

અમદાવાદ- કોરોનાને લીધે છેલ્લા બે વર્ષમાં યુનઆિની ફાઇનલ પરીક્ષાઓ ઓનલાઈન મોડમા લેવાઈ છે તેમજ મેરટિ બેઝ પ્રમોશન આપવામા આવ્યા છે ત્યારે આઇઆઇએમ અમદાવાદે પોતાના મહત્વના બે વર્ષની પીજી પ્રોગ્રામ એવા એમબીએમાં પ્રવેશ માટે નયિમોમાં ધરખમ ફેરફાર કરતા બેચલર ડગ્રિીનુ માપદંડ જ દૂર કરી દીધુ છે.આ વર્ષે એમબીએમાં પ્રવેશ માટે વદ્યિાર્થીના બેચલર ડગ્રિીના પરણિામને ધ્યાને જ લેવામા નહી આવે.આ વર્ષે માત્ર ધો.૧૦ ,૧૨ અને ઉમેદવારના વર્ક એક્સપીરયિન્સ અને કેટ સ્કોરને જ પ્રવેશ માટે ધ્યાને લેવાશે.

કોરોનાને લીધે ઘણી યુનઆિે યુજીમાં ફાઇનલ પરીક્ષાઓ યોગ્ય રીતે ન લઈ શકતા તેમજ ઘણી યુનઆિેએ પાસ પ્રમોશનનું સરટફિકિટ વદ્યિાર્થીઓને આપતા આઇઆઇએમમાં પ્રવેશ માટેની કેટના એલજિબિલિીટી ક્રાઇટેરયિામાં કેટ કમટિીએ મોટો ફેરફાર કરતા બેચલર ડગ્રિીના મનિમિમ પર્સેન્ટેજની જોગવાઈ દૂર કરી હતી.જેને પગલે આઇઆઇએમ અમદાવાદની એડમશિન કમટિી દ્વારા પણ

૨૦૨૨-૨૪ના પીજીપી એમબીએ પ્રવેશ માટેના નયિમોમાં મહત્વનો ફેરફાર કર્યો છે.જે મુજબ આ વર્ષે એમબીએ પ્રવેશ માટે ઉમેદવારની બેચલર ડગ્રિીના પરણિામને એડમશિન શોર્ટલસ્ટિંગિ માટે ધ્યાને નહી લેવાય. વદ્યિાર્થીના બેચલર ડગ્રિીના પરણિામ વગર જ એકેડેમકિ રેટંગિ સ્કોર તૈયાર કરાશે. આ વર્ષની નવી જાહેર કરાયેલી પ્રવેશ ફોર્મ્યુલા મુજબ ધો.૧૦,૧૨ અને ઉમેદવારના વર્ક એક્સપિરિયિન્સને રેટંગિ સ્કોરમાં ધ્યાને લેવાશે અને જેનો સ્કેલ ૨૫ રાખવામા આવશે પરંતુ પ્રો રેટા મુજબ ગત વર્ષની જેમ ૩૫ પોઈન્ટ જ ગણવામા આવશે. જેમાં ગત વર્ષની જેમ બેચલર ડગ્રિીના માર્કસનુ કમ્પોનેન્ટ ધ્યાને નહી લેવાય.જ્યારે વદ્યિાર્થીએ આપેલી કેટ પરીક્ષાના સ્કોરને ૬૫ ટકા વેઈટેજ અપાશે. નવી ફોર્મ્યુલા મુજબ પ્રો રેટેડ એકેડેમકિ રેટંગિ સ્કોરના ૦.૩૫ અને નોર્મલાઇઝ્ડ ઓવરઓલ કેટ સ્કોરના ૦.૬૫ મુજબ કમ્પોઝટિ સ્કોર તૈયાર કરાશે.આમ આ વર્ષે એમબીએ પ્રવેશ માટે બેચલર ડગ્રિીના ક્રાઇટેરયિાને જ દૂર કરી દેવાયો છે.જો કે ઉમેદવારે ઈન્ટરવ્યુ સમયે યુનનિુ ડગ્રિી સરટફિકિટ અથવા માર્કશીટ સરટફિકિટ અથવા યુનકિોલેજમાંથી અપાયેલું પાસંગિ ઈકવીલેન્ટ સરટફિકિટ રજૂ કરવુ પડશે.

પૂર્વ વસ્તિારમાં સાયકલ ટ્રેક નુ આયોજન, સ્વેચ્છાએ દબાણ હટાવ્યા

વડોદરા- વડોદરા શહેરના પૂર્વ વસ્તિારમાં ટ્રાય આકારમાં સાયકલ ટ્રેક નું નર્મિાણ થવા જઇ રહ્યું છે. ત્યારે સ્ટેન્ડગિ કમટિીના ચેરમેને ટીમને સાથે રાખી સાયકલ ટ્રેકનું નરીક્ષણ સાથે નડતરરૂપ દબાણો દૂર કરવા સૂચના અને સ્વચ્છતાની ઝુંબેશ હાથ ધરી હતી.

વડોદરા શહેરના આજવા અને વાઘોડયિાને જોડતા ટ્રેક પર સરદાર એસ્ટેટથી મહાવીર ચાર રસ્તા, સુલેમાન તીન રસ્તો, ઉમા અને વૃંદાવન ચાર રસ્તાથી સરદાર એસ્ટેટ સુધી ત્રકિોણાકાર સાયકલ ટ્રેકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 1.88 કરોડના ખર્ચે લગભગ ચાર કલિોમીટર લાંબો સાયકલ ટ્રેક બનાવવામાં આવશે. કોરોનાના સમયમાં લોકો સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃત બન્યા છે. આ વસ્તિારમાં સાયકલ ટ્રેકની સુવધિા શરૂ કરીને ખેલાડીઓને ફાયદો થાય તે હેતુથી આ સાયકલ ટ્રેકનું નર્મિાણ થવા જઇ રહ્યું છે. 36 મીટર પહોળા રોડ પર જ્યાં કાચો રસ્તો હતો ત્યાં સાઇડ રોડ પર સાઇકલ ટ્રેક બનાવાશે. માત્ર સાયકલ સવારોને લઈ જઈ શકે તેવા વાહનો સવિાયના વાહનોને ચલાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. રોડ પર સાયકલ ટ્રેક માટે સાઇન બોર્ડ મુકવામાં આવશે. ત્યારે આજરોજ સ્ટેન્ડગિ કમટિીના ચેરમેને એન્જનિયિર, વહીવટી વોર્ડ, કોર્પોરેટર અને સંગઠન સહતિના અગ્રણીઓને સાથે રાખી સાયકલ ટ્રેકનું નરીક્ષણ કર્યું હતું. અને રસ્તામાં આવતા દબાણો સ્વેચ્છાએ દૂર કરવા જરૂરી સૂચન સાથે નડતરરૂપ દબાણો પણ દૂર કર્યા હતા. જેથી માર્ગ ઉપર સ્વસ્થતાની સાથે વાહન ચાલકોને સ્પષ્ટ વઝિન પણ મળી રહે.

કોરોનાના કારણે લગ્નોમાં પહેરવામાં આવતા સાફાના વેચાણમાં 50 ટકાનો ઘટાડો

સુરત- હાલમાં લગ્ન સઝિન ચાલી રહી છે પંરતુ કોરોનાના કારણે આ વર્ષે પણ લગ્નોમાં વધ્નિ નડી રહ્યું છે. સરકારી ગાઈડ લાઇન મુજબ લગ્નોમાં 150 જેટલા લોકોની જ પરમશિન આપી છે જેની સીધી અસર લગ્નોની સઝિનમાં ચાલતા બઝિનેસ પર પણ પડવા પામી છે. જેમાંથી એક બઝિનેસ લગ્નના સાફા અને પાઘડીનો પણ છે જેમાં 50 ટકા જેટલી અસર થઈ છે. લગ્નમાં પાઘડી અને સાફા પહેરવાનો રવિાજ પહેલા ઘણા ઓછા સમાજમાં હતો. પરંપરાગત સાફા લગ્નોમાં પતિા, ભાઈઓ અને વરરાજા પહેરતા હતા પરંતુ હવે દરેક કોમ્યુનટિીમાં સાફા વપરાય છે. એક ફેશન બની ગઈ છે એટલે લોકો લગ્નોમાં સાફા મંગાવતા હોય છે. જેટલા માણસો તેટલા સાફા આવતા હોય છે અને તે ભાડેથી લાવતા

હોય છે. જો કે કોરોનાના કારણે લગ્નોમાં વધુ માણસો પર પ્રતબિન્ધ આવી ગયો છે જેના કારણે સાફાના વ્યાપારમાં 50 ટકા જેટલું નુકશાન થવા પામ્યું છે. ઘણા ઓર્ડરો કેન્સલ પણ થઈ ગયા છે. આ અંગે સાફાના વ્યાપારી તારાચંદભાઈએ કહ્યું કે "અમે લગ્નોમાં સાફા ભાડે આપવાનું અને વેચાણનું કામ કરીએ છે.

गऊ भारत भारती
परिवार
प्रकाशक/ प्रधान संपादक
संजय रमाशंकर शर्मा
सलाहकार संपादक
डॉ . विजय गुप्ता (कृषि वैज्ञानिक),
राजेश विक्रांत (स्तंभकार हिंदी दोपहर का सामना),
प्रेम कुमार (सलाहकार संपादक)
विशाल भगत (सलाहकार संपादक)
संवाददाता- फिरोज खान, अब्दुल कादिर
विज्ञान विभाग- साई सामी ग्रुप
भूपेंद्र- फोटोग्राफर
पृष्ठ सज्जा- अमोल गुडेकर ग्राफिक्स
अनिल नलावडे- वितरण व्यवस्था
मंत्रालय वितरण- सुचित कुमार
सभी पद अवैतनिक है
संपर्क- गाला नं. 430, अस्मी इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, आर-5, 4था माला, नियर आशिर्वाद इंडस्ट्रीयल इस्टेट, राममंदिर (पश्चिम), मुंबई- 400104
मो- 9768372509.

दिल्ली, मुंबई में कोरोना ग्राफ में गिरावट, सख्त गाइडलाइन दिखा रही है असर?

देश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार अपना असर दिखा रही है. आज एकबार फिर देश में कोरोना के तीन लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं. इसके अलावा ओमीक्रॉन के भी मामलों की संख्या देश में १० हजार को पार कर चुकी है. वहीं महानगरों की बात करें तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार जरा घटती दिखाई दे रही है. दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है. वहीं मुंबई में भी कोरोना की रफ्तार कम हो रही है. शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के १०,७५६ नए मामले सामने आए तो वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक दिन में कोरोना केस की संख्या ५,००८ रही. दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी घटकर १८.०४ फीसदी हो गया है. तो मुंबई में भी लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली. वहीं दोनों महानगरों में

कोरोना से मौत के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में पिछले २४ घंटों में ३८ मरीजों की मौत हुई है. तो वहीं मुंबई में ये आंकड़ा १२ का रहा. गुरुवार को दिल्ली में १२,३०६ नए कोरोना केस सामने आए थे जबकि ४३ लोगों की मौत हुई थी. वहीं मुंबई में गुरुवार को ५,७०८ नए कोरोना केस मिले थे और १२ लोगों की मौत हुई थी. पिछले दिनों के आंकड़ों से साफ है कि दोनों ही महानगरों में कोरोना पर कुछ हद तक कमी आती दिख रही है. हालांकि दूसरे कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना विस्फोटक होता दिख रहा है. केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते दिख रहे हैं.

रैली और रोड शो पर जारी रहेगी रोक, चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली- भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर शनिवार को बैठक की. बैठक में चुनावी रैली, रोड शो, जुलूस पर पाबंदी जारी रखने का बड़ा फैसला लिया. सूत्रों के अनुसार आयोग ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलो और कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए फिलहाल चुनावी रैली में पाबंदी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया. आयोग की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा सभी आयुक्त और उपायुक्त भी शामिल हुए थे. इसके अतिरिक्त पांचों राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने भी आयोग की बैठक में फैसला लिया. चुनाव आयोग की इस बैठक में पांचों राज्यों के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और मुख्य स्वास्थ्य सचिव वर्चुअल रूप से शामिल हुए. बैठक में कोरोना के हालात पर समीक्षा की गई जिसके बाद चुनावी रैली पर पाबंदी को बढ़ाने का फैसला लिया गया है. गौरतलब है कि नौ जनवरी को पांचों राज्यों के चुनानी कार्यक्रम की घोषणा के

दौरान १५ जनवरी तक रैली, नुक्कड़ सभाओं, पद यात्रा, साइकिल रैली पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था. १५ जनवरी को समीक्षा करने के बाद आयोग ने इस पाबंदी को लागू रखा, लेकिन राजनीतिक दलों को थोड़ी राहत देते हुए बंद कमरे में अधिकतम ३०० लोग या फिर कमरे की ५० प्रतिशत क्षमता के साथ सभा आयोजित करने की अनुमति दी थी. सूत्रों का कहना है कि आज की बैठक में आयोग पाबंदी में कुछ छूट दे सकता है.

सूत्रों की मानें तो पहले चरण के चुनाव का प्रचार इस बार भी पहले की ही तरह ७२ घंटे पहले ही खत्म होगा और उम्मीद है कि इस बार इससे संभवत: एक सप्ताह पहले चुनावी रैली पर लगी पाबंदी को खत्म कर दिया जाएगा. हालांकि सूत्रों का मनना है कि अलग छूट मिल भी जाती है तो प्रचार में पाबंदी लगी रहेगी. आपको बता दें कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव १० फरवरी से शुरू होकर ७ मार्च तक चलेंगे और सभी राज्यों की मतगणना १० मार्च को होगी.

कोरोना के कम होते मरीजो के बीच BMC बगीचों, पार्कों को फिर से खोल सकती है

स्कूलों और जूनियर कॉलेज के लिए शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने की घोषणा के एक दिन बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम ने शुक्रवार, २१ जनवरी को कहा कि वह शहर में उद्यानों और पार्कों को फिर से खोलने की अनुमति देने की योजना बना रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुंबई में कोरोना के मामले लगातार काम होते जा रहे है। जिसे देखते हुए ँशण ने ये फैसला किया हैं। बीएमसी अधिकारियों ने कहा कि वे अगले कुछ दिनों में शहर में लगाए गए प्रतिबंधों में और ढील देने के लिए राज्य सरकार के एक नए आदेश की उम्मीद कर रहे हैं। जैसा कि जनवरी

के पहले सप्ताह में कोरोनोवायरस के मामलों में तेजी देखी गई, महाराष्ट्र सरकार ने ८ जनवरी को कई प्रतिबंधों की घोषणा की, जिसमें रात ११ बजे से सुबह ५ बजे तक सार्वजनिक आंदोलन पर प्रतिबंध, थीम पार्कों को बंद करना, खुले स्थान, पर्यटन स्थल आदि शामिल हैं।

नागरिक अधिकारी ने कहा कि सीमित समय के साथ उद्यानों, पार्कों, पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने जैसे प्रतिबंधों में कुछ और ढील दी जा सकती है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लिए गए निणऱ्य के बाद ही घोषणा की जाएगी। साथ ही रेस्टोरेंट, होटलों के समय में भी ढील दी जा सकती है।

यूपीटीईटी परीक्षा की अब सीएम योगी ने खुद संभाली कमान, यहां जानें दिशा-निर्देश

नई दिल्ली- लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कल यानी कि २३ जनवरी को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, यूपीटीईटी होने जा रही है। इसके तहत पहली शिफ्ट कल सुबह १० बजे से शुरू हुई थी। वहीं नवंबर में एग्जाम लीक होने की वजह से परीक्षा कैंसिल हो गई थी। इसके चलते इस बार परीक्षा में सुरक्षा के इंतजाम को और बढ़ा दिया गया है। वहीं एग्जाम में कोई चूक न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हस्तक्षेप किया है और अधिकारियों को परीक्षा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोविड-१९ पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भी अलग से निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक, इन उम्मीदवारों को भी परीक्षा देने की अनुमति होगी। लेकिन इनके लिए अलग कमरे में बैठने की सुविधा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और अपर प्राइमरी सरकारी में बतौर शिक्षक की नियुक्ति के लिए इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश हैं। यूपीटीईटी परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवार आइए जानते हैं निर्देश। परीक्षा में देरी से बचने और समय पर जांच कराने के लिए उम्मीदवारों को पेपर शुरू होने से कम से कम १ घंटे पहले यूपीटीईटी परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए। परीक्षा में जांच

के लिए एक वैलिड फोटो पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि लेकर जाना होगा। परीक्षा में नकल, धोखाधड़ी, या पेपर लीक जैसे अनुचित साधनों का उपयोग सख्त वर्जित है। यहां तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी सीएम की ओर से बयान जारी किया है, जो लोग इस तरह के किसी भी साधन में लिप्त पाए जाएंगे, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल, नवंबर में व्हाट्सएप पर पेपर लीक होने के बाद परीक्षा कैंसिल हो गई थी। इसके चलते इस बार सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला है। परीक्षा हॉल के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुंबई में खराब हो रहा वातावरण

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा क्षेत्रीय वायु प्रदूषण के स्तर के एक नए विश्लेषण से पता चला है कि समुद्र की निकटता ने वित्तीय राजधानी मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने में मदद नहीं की है। आसान शब्दों में कहें तो बढ़ता वायु प्रदूषण केवल सर्दियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब मुंबई में भी यह साल भर की समस्या है। बुधवार, १९ जनवरी को जारी यह विश्लेषण, १ जनवरी, २०१९ से ९ जनवरी, २०२२ की अवधि के लिए PM२.५ एकाग्रता में वार्षिक और मौसमी रुझानों का आकलन था। सीएसई के वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बताते हुए कहा कि २०१९ से २०२१ के बीच मुंबई में खराब दिनों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि अच्छे दिनों में २० फीसदी की कमी आई है। सीएसई के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि मुंबई में खराब वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या बढ़ रही है। शहर में, पूर्व-मध्य मुंबई में कुर्ला में केवल ५५ प्रतिशत डेटा था जबकि उत्तरी मुंबई में मलाड (पश्चिम) ६८ प्रतिशत के साथ आया था। सीएसई द्वारा इसी विश्लेषण के एक हिस्से के

रूप में, महाराष्ट्र के अन्य शहरों की तरह, मुंबई ने भी २०२० के दौरान (जब लॉकडाउन थे) एक प्रारंभिक गिरावट के बाद वार्षिक पीएम२.५ स्तरों में एक बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत दिया है, जिसमें एक पलटाव और एक बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। १० सबसे पुराने स्टेशनों पर आधारित दैनिक AQI विश्लेषण २०१९ और २०२१ के बीच शहर में अच्छे AQI दिनों की संख्या में २० प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है जबकि खराब या बहुत खराब AQI वाले दिन दोगुने हो गए हैं। सदिऱ्यों के दौरान दक्षिण मुंबई में शहर के भीतर सबसे खराब हवा होती है। दिसंबर २०२१ में, SoBo के स्टेशनों ने शहर के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी अधिक PM२.५ स्तर की सूचना दी। १३४ माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के मासिक औसत के साथ मझगांव शहर का सबसे प्रदूषित इलाका था, इसके बाद नेवी नगर, कोलाबा (१२४ माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब), कुर्ला (१०१ माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब), विले पार्ले (पश्चिम) (१०१) था। माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब) और वर्ली (९७ माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब)।

आरे के जंगल में रात ११ बजे से सुबह ६ बजे तक वाहनों की अनुमति नहीं

आरे जाने वाले मुख्य मार्ग को रात ११ बजे से सुबह ६ बजे तक बंद कर दिया जाएगा ताकि क्षेत्र में वन्यजीवों के जीवन में मानवीय गतिविधियों को हस्तक्षेप करने से रोका जा सके। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने सोमवार को इस बात की जानकारी

दी। हीरानंदानी, पवई, जोगेश्वरी, फिल्टरपाड़ा आदि जाने वाले वाहन आरे कॉलोनी में सड़क का उपयोग करते हैं। इससे पिछले कुछ वर्षों में प्रदूषण में वृद्धि हुई है। तेंदुआ जैसे जानवर रात के समय जंगल में स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते हैं। चालक और तेंदुआ आमने-सामने आ जाए तो दोनों के बीच संघर्ष की संभावना बनी रहती है। इसलिए रात के समय बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

RNI No. MAHMUL/2015/65928
मो.: 9768372509
गऊ वंश पर आधारित प्रथम राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में।

गऊ भारत भारती
आर-5, 4था माला, गाला नं. 430, अस्मी इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, नियर आशिर्वाद इंडस्ट्रीयल इस्टेट, राममंदिर स्टेशन (पश्चिम), गोरेगांव, मुंबई- 400104 ईमेल- gaubharatbharti@gmail.com www.gaubharatbharati.com

क्या आप गौ माता के प्रॉडक्ट बनाते है पुरे भारत में मार्केटिंग और वितरण लिए संपर्क करे
गऊ भारत भारती
Email - gaubharatbharti@gmail.com
फोन - 8850 33 7237
व्हॉट्सअॅप नंबर - 79774 21335

मुस्लिम महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी, मुंबई पुलिस ने हरियाणा से तीन को दबोचा

मुंबई- मुंबई पुलिस ने क्लब हाउस ऐप पर चैट के सिलसिले में हरियाणा से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी की गई थी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई अपराध शाखा के साइबर थाने के कमिऱ्यों ने बृहस्पतिवार रात इन लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से दो आरोपियों को आज दिन में अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर शहर की पुलिस को मामले में गिरफ्तारी के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया कि मुंबई पुलिस को बधाई। उन्होंने क्लब हाउस चैट के खिलाफ भी कार्रवाई की और कुछ

गिरफ्तारियां भी की गई हैं। नफरत को ना कहें। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को क्लब हाउस ऐप और सर्च इंजन गूगल को पत्र लिखकर कथित ऑडियो ग्रुप चैट के आयोजक के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसमें कथित तौर पर ''मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी की गई थीं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने जांच के तहत 'ग्रूप ऑडियो चैट' के कुछ सदस्यों की पहचान भी की, जिसमें दोनों समुदायों के पुरुष और महिलाएं शामिल थे। एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई के एक संगठन ने 'क्लब हाउस ऐप' के संबंध में बुधवार को शहर की पुलिस से शिकायत की थी और उसे निष्क्रिय करने तथा मामला दर्ज करने की मांग की थी। दिल्ली महिला आयोग ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर एप पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके कुछ घंटों के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उस कथित ऑडियो चैट समूह के आयोजक के बारे में विवरण मांगने के लिए क्लबहाउस एप को पत्र भी लिखा है, जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणियां' की गई थीं।

Gaukkart
GAUKKART IS AN INDIAN E-COMMERCE COMPANY

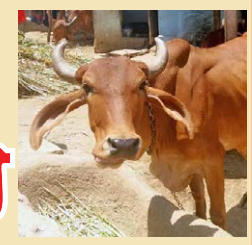

अपील
स्थापना दि. 19-12-2002 रजि नं. 12344/एफ/7802/सोलापूर

श्री राधे कृष्ण गौशाला
को इस समय दान की बहुत आवश्यकता है पूरी गौशाला में चारे-पानी की बहुत कमी है। सभी गौभक्तों से निवेदन है कि इस गौशाला को मदद करें।

Bank of India
071920100000076
(IFSC Code: BKID 0000719)
Central Bank 3167615243
(IFCS Code: CBINO282523)
Pan No.: AABAR3881N
shriradhekrishngoushala@gmail.com
www.shreeradhekrishnagoshala.in

श्री शामराव विठ्ठल बाबर
संस्थापक
९३२४०८४९३१

अपीलकर्ता
गऊ भारत भारती

यह साप्ताहिक स्वामी मुद्रक व प्रकाशक संजय रमाशंकर शर्मा द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. ३/४, अमीन इंडस्ट्रीयल इस्टेट, सोनावाला क्रॉस रोड नं. २, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- ६३, महाराष्ट्र से मुद्रित करवाकर, इर्ला सोसायटी रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई- ४०० ०५६ महाराष्ट्र से प्रकाशित किया।
■ संपादक - संजय रमाशंकर शर्मा, संपादकीय कार्यालय- आर-५, ४था माला, गाला नं. ४३०, अस्मी इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, नियर आशिर्वाद इंडस्ट्रीयल इस्टेट, राममंदिर स्टेशन (पश्चिम), गोरेगांव, मुंबई- ४००१०४ मो- ९७६८३७२५०९. फोन- ०२२-६९९९९४६६
■ कानूनी सलाहकार- अॅड. देवेंद्र सिंह / अॅड. सुरेश पांडेय (किसी भी विवाद का न्यायालय क्षेत्र मुंबई होगा) इस अख़बार में प्रकाशित लेख, समाचार से संपादक का सहमत होना जरूरी नहीं है। ■ gausevatimes@gmail.com ■ Email: gaubharatbharti@gmail.com RNI No. MAHMUL/2015/65928